



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 214]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 1987/आस्विना 23, 1909

No. 214]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1987/ASVINA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्षण में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

वार्षिक वाचालय

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1987

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 28 ई-टी (पी एन)/87

विवरण—1 अक्टूबर, 1988 से 31 दिसम्बर, 1990 तक समुक्त राज्य
प्रमोटरों, पूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्थाया,
फिनैंड, स्टीडन, नार्वे और कनाडा को बुने मामान्य लाइसेंस
के प्रत्यांत प्रोग्रामों और सनाई से तैयार किए गए वस्त्रों को
नियंत्रण करने के लिए स्वीम।

का. सं. 2/95/87-ई-1—यह स्वीम तैयार प्रोग्रामों और सलाइ
से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मरमों के व्युत्तर राज्य प्रमोटरों, पूरोपीय
आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणराज्य संघ, फ्रान्स, इटली,
बेनेलक्स, यू. के, आयरिश। गणराज्य, ऐरिंग्क, फ्रीम, पुर्नगाल और स्पेन)
आस्ट्रिया, फिनैंड, स्टीडन, नार्वे और कनाडा को 1 अक्टूबर, 1988
से 31 दिसम्बर, 1990 तक की भवधि के लिए नियंत्रण से संविनित है।

2. योजना को प्रणालित करने के लिए अधिकारण

जब तक आव्याय रूप से निवेद्य न दिया जाए तब तक परिधान नियंत्रण संबंधीन परिवर्द्ध (ई पी सी) नहीं दिया जायेगा इन्हाँसी का आवेदन करेंगी और इस योजना के अन्तर्गत आंतरिक वात्री सभी प्रांगणों और सलाइ से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवाषक प्रकाशन करेंगी, परन्तु सलाइ से बुने हुए ऊनी वस्त्रों की इकाई का आवेदन, उन और ऊनी नियंत्रण संबंधीन परिवर्द्ध (डब्ल्यू.एड डब्ल्यू.ई.पी.सी) नहीं दिया जाया जाएगा। लेकिन सलाइ से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन परिधान नियंत्रण संबंधीन परिवर्द्ध द्वारा किया जाना चाहिए। इन योजना के अन्तर्गत आंतरिक वात्री उत्पादों की व्येगियों को नूतनी परिधान नियंत्रण संबंधीन परिवर्द्ध और डब्ल्यू.एड डब्ल्यू.ई.पी.सी के साथ उपलब्ध है। सरकार को यह अधिकार होगा कि योजना के प्रारंभ के लिए अधिकारणों के संबंध में जहाँ और जैसा उचित समय परिवर्तन कर सकता है।

(2) नियंत्रण इकाई के लिए ही अनुभव होनी जो सक्रम परिवर्द्ध अधिकारियों के साथ जोड़ा जाए।

3. आवेदन की प्रणाली और माला

(1) यदि विचाराधीन वर्ष के पहले के प्रत्येक तीन वर्षों के दीर्घन नियंत्रण विक्लित स्तर से लगातार 91% या अधिक होता है तो कृष्ण

श्रेणियों की सुपर फास्ट श्रेणी के रूप में घोषित किया जाएगा। उत्तराखण्ड 1688 वर्ष के लिए 1984, 1985 और 1986 का नियंत्रित निष्पादन संरक्षित होगा। बरस आयुक्त इन श्रेणियों को बर्गीकृत और अधिकृत करेंगे।

(2) सुपर फास्ट श्रेणी के अधीन नियंत्रित के लिए मात्रा का 85% प्रत्येक के सामने उल्लिखित दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार अधिकृत किया जाएगा :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का %
(क) भूतकालीन निष्पादन (वीपीई)	70
(ख) विनिर्माता नियंत्रक (एम ई ई)	10
(ग) केन्द्रीय/राज्य निगम	2
(घ) विना कोटे वाले नियंत्रक	3
	85

(3) सुपरफास्ट श्रेणी की शेष 15% मात्रा के लिए जो आजकल हुल नियंत्रित के 5% भगाना है, सबू पैमाना उच्चमों सहित नए नियंत्रितों को हिताएं प्रदान करने के साथ-साथ उसका आवंटन खुली संविदा प्रणाली के इच्छित किया जाएगा। इसे प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जा रहा है।

(4) सुपरफास्ट श्रेणी से इतर श्रेणियों के लिए, नियंत्रित के लिए मात्रा का आवंटन प्रत्येक के सामने संकेतित दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का %
(क) भूतकालीन निष्पादन	65
(ख) पहले आए तो पहले पाए (सबू प्रावेश)	20
[एक सी एक एस (एस एस)]	10
(ग) विनिर्माता नियंत्रक (एम ई ई)	2
(घ) केन्द्रीय/राज्य निगम	3
(ज) विना कोटे वाले नियंत्रक	
	100

(5) हवार उब और जैसे उचित समझी उसे द्विपक्षीय समझाते हैं इस दराना का उपयोग करने का अधिकार होगा।

4 आवंटन वर्ष का विभाजन तथा अवधियों के बीच मात्रा का संविभाजन

(1) ए.पी.ई.एम.ई.ई.ओ.एस न्यू ई प्रणाली के मामले में, वर्ष को वी इच्छियों में बांटा जाएगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मई तक और दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। किए गए कुल 144 दिन का कम से कम 50% प्रथम अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त में लाया जाना चाहिए। शेष 50% का उपयोग द्वितीय अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। प्रत्येक अवधि के अन्त में कोई भी अप्रूक्त बच्ची हुई मात्रा रखते ही अमर्यापित हो जाएगी। लेकिन नींवें उल्लिखित पैरा 18 (2) के उपर्योग के अनुमार आवंटन बैध किया जाए।

(2) (1) केन्द्रीय/राज्य निगम (2) सुपरफास्ट के रूप में बर्गीकृत कृषि श्रेणियों के लिए खुली संविदा प्रणाली (3) एक सी एक एस (सबू प्रावेश) प्रणाली के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांटा जाएगा। अर्थात् बुर्ज और सलाई से बुर्न मध्ये दोनों के लिए जनवरी-मई और जून-सितम्बर। केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली, संविदा प्रणाली और एक सी-

एक एस (सबू प्रावेश) प्रणाली के अधीन मात्रा वो अवधियों में 70:30 के अनुपात से बांटी जाएगी। वार्षिक स्तर का 70% प्रथम अवधि में और शेष 30% द्वितीय अवधि में आवंटित किया जाएगा। समृद्ध राज्य प्रमार्का और कमादा के लिए प्रथम अवधि की सक्रिय मात्रा खुली संविदा प्रणाली और एक एस लम्बा आवेदन प्रणाली में 1 जनवरी को खोली जाएगी। नियंत्रितों को स्टैगर करने के उद्देश्य से अन्य कोटे के दोनों के लिए मात्रा 15 जनवरी से खोली जाएगी।

(3) उपर्युक्त प्रतिशत को विवेशी बाजार के उपान को देखते हुए सरकार पुनः समर्जित कर सकती है।

5. खण्डों को आगमित रखना

(1) एक सी एक एस (सबू प्रावेश) प्रणाली खुली संविदा प्रणाली के लिए सुपर फास्ट श्रेणी और केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली के मामले में जहां पर आवंटन सलाई से बुने हुए पीशाकों को खुली हुई (बोक्स) पीशाकों के साथ मिला दिया जाता है वहां पर उनवें वार्षिक स्तर की 10% की मात्रा नियंत्रित रखी जाएगी।

(2) वज्रों की पीशाकों के लिए अंतिम तिथि को सभी श्रेणियों में उपलब्ध मात्राओं का 10% सुरक्षित रखा जाएगा।

(3) उनीं पीशाकों के लिए यह आरम्भ विविडिकृत देशों और श्रेणी की मात्राओं की शर्त के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में नीति की घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

6. भूतकालीन निष्पादन प्रणाली

(1) भूतकालीन निष्पादन हुक्कारी की परिणाम करने के लिए अधिकरण :— प्रत्येक नियंत्रित के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा की हुक्कारी की गणना के लिए अधिकरण वस्त्र परिषान नियंत्रित संबंधीन परिवर्त ए.पी.ई.सी.सी., नई दिल्ली होगी। वस्त्र प्राप्ति इस संबंध में ए.पी.ई.सी.के कार्यकारी संबंधीन करेगा।

(2) भूतकालीन निष्पादन हुक्कारी के लिए मात्रा पद्धति :— 1981 वर्ष के लिए भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अधीन की नियंत्रित मात्रा में आवंटन के लिए केवल तब पात्र होगा जबकि उसने दो वर्षों दौरान 1985 और 1986 में से किसी भी एक वर्ष के दौरान संबंधीन देश/विदेशी में वास्तविक पीतलयान द्वारा नियंत्रित निष्पादन किया हो। बाद के 1989 और 1990 वर्षों के लिए, भी भी ए.पी.ई.की परिणाम के लिए आधार अवधि कमशा: 1986 और 1987, 1987 और 1988 होगी।

(3) आधार अवधि और सीलिंग :— 1988 के लिए भूतकालीन निष्पादन हुक्कारी, 1985 और 1986 की आधार अवधि के दौरान नियंत्रित के भीसत्र मूल्य के आधार पर प्रत्येक देश/विदेशी समूह के युक्तानुपात गे लिए स्थिरित किया जाएगा। बाद के 1989 और 1990 वर्ष के लिए आधार अवधि कमशा: 1986-87 और 1987-1988 होगी। भूतकालीन निष्पादन हुक्कारी का युक्तानुपात आवंटन प्रत्येक देश/विदेशी में आधार अवधि के दौरान नियंत्रित के भीसत्र वार्षिक नियंत्रित निष्पादन के बराबर अधिकतम उत्तम सम्म के अधीन होगा। किसी भी अवधिकार नियंत्रित की हुक्कारी में बाद में दोनों दोनों भी परिवर्तन के मामले में इथनृत मात्रा की पूर्ण प्रतियोगी दृष्टिने की आवश्यकता नहीं है लेकिन नियंत्रित की हुक्कारी में उचित सम्बंधन कर दिया जाएगा।

भूतकालीन निष्पादन हुक्कारी का हस्तांतरण :— भूतकालीन निष्पादन हुक्कारी संगत वर्ष की 30 नितम्बर तक किसी भी समय या तो पूर्ण सूप से या आंशिक हृप से पीशाकों के अस्थ पंजीकृत नियंत्रित को निम्ननियंत्रित शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जा सकती है।

(क) भूतकालीन निष्पादन हुक्कारी के सभी हस्तांतरण के बारे में द्वारा 10 प्रतिशत बैंक गारंटी करने पर ही अनुमित किए जाएंगे।

(ख) हस्तांतरण को हस्तांतरित मात्रा के नियीत के लिए 60 दिन का संगत प्रबन्ध जिसमें हस्तांतरण किया गया है उसकी अंतिम तिथि तक जो भी पहले हो, की ग्रन्थात दी जाएगी।

(ग) जिस नियांतक से अपनी हकदारी एक विशेष देश/ब्रेणी में दूसरे नियांतक को हस्तांतरित की हो, वह उसी देश/ब्रेणी में किसी अन्य नियांतक से भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण पूर्ण या प्रांशिक रूप में मानने के लिए पास नहीं होगा।

(घ) जिस नियांतक ने पूर्ण या प्रांशिक रूप में विशेष देश/ब्रेणी में हिंदू अन्य नियांतक के हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त करती है तो वह उसी देश/ब्रेणी में अन्य नियांतक को किसी भी हकदारी का हो हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(इ) भूतकालीन निष्पादन का हकदार व्यक्ति जो किसी देश/ब्रेणी में खुली संविदा "पहले" आए थे "पहले पाए" के लघु आवेदनों की पद्धति के अन्तर्गत किसी हकदारी को प्राप्त करता है वह इस प्रकार के छंटे आवेदनों की हकदारी प्राप्त करने के बावजूद उन देश/ब्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) हस्तांतरी के पास हस्तांतरित हकदारियों अन्य सभी प्रकार ने उहाँ नियम भारतीयों के अधीन होंगे, जो हस्तांतरण के लिए लागू हैं।

7. सुपरकास्ट श्रेणियों के लिए खुली निविदा पद्धति

(1) इस पद्धति के अधीन बन्द निविदाओं के आधार पर मात्राएं न बढ़ित की जाएंगी। नियांतकों को आवेदन मात्रा पर सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रांशियम को दर्शाते हुए बन्द निविदाएं भेजती होंगी। आवेदन पर शस्त्र आयुक्त द्वारा घोषित किए जाने पर सीलिंग मात्रा के अन्तर्गत भेजे जाएंगे।

(2) आवंटन भेजे गए प्रांशियम के आधार पर निश्चय किया जाएगा और उस दिन जबकि उपलब्ध मात्राएं अभिवृत से अधिक हैं तो पात्रता का निर्णय उच्च प्रांशियम बोली के आधार पर होगा।

(3) नियांतकों को न्यूनतम नियांत मूल्य पर माल का नियांत करना अनिवार्य होगा जो कि सरकारी बोली तथा नियांतकों द्वारा लिए गए 3 प्रांशियम को मिला कर होंगी। सरकारी बोली गत वर्ष के होतान इन श्रेणियों में घोस्तन एक मूल्य बरूपी के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(4) इस पद्धति के अधीन आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

(क) नियांतकों को परिधान नियांत संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत होना चाहिए (अथवा उन्हें हुए वस्त्रों के लिए उन एवं उनकी वस्त्र नियांत संवर्धन परिषद्)।

(ख) एक नियांत से एक दिन के लिए एक देश/ब्रेणी के लिए केवल एक ही आवेदन-पत्र अनुमेय होगा। लेकिन, एक से अधिक आवेदन पत्र दिया जा सकता है वर्तमान कि इन आवेदन-पत्रों में दो गई कुल मात्रा वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चय की गई अनुबन्ध मात्रा सीलिंग के अन्तर्गत है।

(ग) इस पद्धति के अन्तर्गत आवंटन 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। इसरी अवधि में आवंटन 60 दिनों के लिए अवधा संबद्ध वर्ष के 31 दिसम्बर, तक इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगा।

(घ) आवंटन के लिए आवेदन-पत्रों के आध परिधान नियांत संवर्धन परिषद् को देश कुल प्रांशियम धनराशि के लिए डिमांड इक्सिट लगा होना चाहिए।

(ङ) सभी पंजीकृत नियांतक जाहे उनकी अन्य हकदारियों किसी भी अन्य पद्धति के अधीन कुछ भी हो, बोली के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

8. पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) पद्धति:

इस पद्धति के अन्तर्गत मात्रा का आवंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदाओं और सख्तपत्रों द्वारा समर्थित आवेदन पत्रों के मध्य किया जाएगा। लेकिन संख्या आवश्यकता पड़ते पर केवल प्रमाणन के समय पर ही प्रस्तुत करना होगा। मात्रा का आवंटन केवल लघु आवेदनों के लिए किया जाएगा जो कि विभिन्न देश/ब्रेणी के लिए वक्त्र अयुक्त द्वारा परिणामात्मक सीमाओं के भीतर नियत किए गए हैं। ऐसी परिणामात्मक सीमाएं उचित समय के भीतर घोषित कर दी जाएंगी। इस पद्धति के अन्तर्गत आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

(1) नियांतकों को परिधान नियांत संवर्धन परिषद (या सलाई से बने हुए उन्होंने वस्त्रों के लिए उन और उनीं वस्त्र नियांत संवर्धन परिषद के साथ) आवेदन पत्र के दिन पंजीकृत होना चाहिए।

(2) एक दिन में एक नियांतक से एक देश/ब्रेणी के लिए केवल एक आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक, लेकिन आवेदन पत्र लिए जा सकते हैं, वशर्तें कि देसे आवेदन पत्रों में आवेदन मात्रा नियांत मात्रक सीमा के भीतर हों।

(3) इस पद्धति के अन्तर्गत आवंटन 80 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। इसरी अवधि में आवंटन केवल 60 दिन या संगत वर्ष की 31 दिसम्बर इसमें से जो भी पहले हो, तक वैध होगा।

(4) आवंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर मंजूर किया जाएगा, और जिस दिन उपलब्ध मात्रा अतिपूर्वकीत हो जाएगी, उस दिन पत्रकार का नियंत उच्च इकाई मूल्य वर्गीयों के आधार पर किया जाएगा।

(5) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वाला नियांतक संबंधित देश/ब्रेणी के लिए पैरा 6(3) के अनुसार यथा परिकलित अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी का कम से कम 50 प्रतिशत का नियांत करने के बाद इस पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उसके लिए भूतकालीन हकदारी के समस्त शेष अन्यायित करने का भी विकल्प होगा कि वह संबंधित देश/ब्रेणी का हो और तब वह पहले आए सो पहले पाए (छोटे आवेदनों) के अन्तर्गत आवेदन करता है वशर्तें कि उसने उस देश/ब्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से जिक्री किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं किया है।

(6) विनियांत-नियांतक हकदारी के बाल को पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र बनने से पूर्व उन्होंने ऐसी हकदारी का पूर्ण-पूरा उपयोग करना पड़ेगा या उसे अन्यायित करना पड़ेगा।

(7) पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) पद्धति के अन्तर्गत आवंटन के उद्देश्य के लिए आवेदक इस संबंध में एक साप्तपत्र देश/ब्रेणी का विवरण 1985-88 के पैरा 120 में यथायापात्रित उसकी किसी भी सहयोगी ने इस पद्धति के अन्तर्गत आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया है और यह कि उसके स्वामित्व के अधीन किसी अन्य स्वामित्व वाली व्यापार संस्था ने भी आवंटन के लिए इस पद्धति के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है। आगे, प्रथम अवधि के आवंटन के लिए आवेदक इस संबंध में भी साप्तपत्र देश/ब्रेणी कोई भी सहयोगी व्यापार संस्था कोई भी भूतकालीन निष्पादन हकदारी नहीं रखता है। तथापि, उचित प्रपत्र में एक समव दिए गए व्याप्तपत्र देश/ब्रेणी के समूह को भी लिया जा सकता है जिसमें आवेदक इंगित करेगा कि एक अध्यावेदनों के समूह के लिए प्रथम आए प्रथम पाए (लघु आदेश) प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन करेगा।

9. विनिर्माता निर्यात पद्धति :

(1) इस पद्धति में वार्षिक स्तर की 10 प्रतिशत तक की मात्रा विनिर्माता निर्यातक को आवंटन की जाएगी।

(2) वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों की वार्षिक स्तर का 8 प्रतिशत आवंटन विया जाएगा। 3 प्रतिशत का स्तर उन नए निर्यातकों के लिए आरक्षित होगा जो संगत वर्ष के दौरान विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करते हैं।

(3) इस पद्धति के अंदर आवंटन हेतु पात्र होने के लिए नए विनिर्माता निर्यातकों को कम से कम 100 मर्शीनें और 150 कारोगरों को रखा जाना चाहिए।

(4) इस पद्धति के अंदर आवंटन के लिए वर्तमान विनिर्माता वस्त्र आयुक्त के पास पात्रपंजीकृत अपनी वर्तमान विनिर्माण क्षमता के आधार पर पात्र होगे। लेकिन, उनको 1989 तक कम से कम 100 मर्शीनें और 150 कारोगर लगाकर अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना भी चाहिए। वर्तमान विनिर्माताओं के लिए इस पद्धति के अंदर आवंटन के लिए पात्रता मानदण्ड 1 जनवरी, 1989 को 100 मर्शीनें और 150 कारोगर होंगे।

(5) वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों के लिए 50% नए आरक्षित स्तर भूतकालीन नियादन के अधार पर आवंटित किया जाएगा और शेष 50% विनिर्माता निर्यातकों की विनिर्माण क्षमता के आधार पर होगा। भूतकालीन नियादन और विनिर्माता निर्यातक पद्धति के अंदर विनिर्माता निर्यातक के लिए कुल आवंटन आधार अवधि के दौरान (उदाहरणार्थ 1988 के दौरान आवंटन के लिए 1985 और 1936) उनकी ध्यासतन वार्षिक निर्यात नियादन का 100% से अधिक नहीं हो। निर्यातक को विनिर्माता निर्यातक हकदारी का कुल आवंटन उसकी विनिर्माता क्षमता से भी अधिक नहीं होगा।

(6) नए विनिर्माता निर्यातकों के लिए आवंटन इनकी विनिर्माता क्षमता के आधार पर किया जाएगा। नए विनिर्माता निर्यातकों के लिए आरक्षित वार्षिक स्तर का 2% में से अनावंटित मात्राएं पहले उन वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों के लिए आवंटित होंगी जिनके पास 100 मर्शीनें से अधिक होते हुए उनकी विनिर्माण क्षमता में कुल मिलाकर कमी हुई है।

(7) वस्त्र आयुक्त इस पद्धति के अंदर आवंटन के लिए पात्रता का फैलाव करेगा जिसके लिए वह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

10. केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित नियमों और केन्द्रीय/राज्य स्तरीय की शिवर सहायी हथकरधा विषय समितियों के लिए वार्षिक स्तर के लिए अधिकार 2 प्रतिशत का विनेन आवंटन किया जाएगा। लेकिन यह आवंटन इन नियमों/उच्च स्तरीय समितियों द्वारा केवल संघ नियमों के लिए होता है। इन प्रणालों के अंदर आवंटन इस शर्त के अंदर नहीं होता कि केन्द्रीय/राज्य नियमों का अपने संरक्षण में उदाहरण करना चाहिए। नियम/शिवर समितियों भी पूर्व नियादन और आवंटन के पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छठे आदेश की पद्धतियों के अंदर न मात्रा के आवंटन के लिए नीति में दी गई गतीयों को पूरा करने के अंदर न पात्र होंगी। वस्त्र आयुक्त नियमों/शिवर समितियों की हकदारी निश्चित करेगा। ऐसे नियम अपने विनिर्माण एकांकों को जिनके पास 1 जनवरी, 1989 से कम से कम 100 मर्शीनें और 150 कारोगर हों, केवल 1989 में इस काटे के आवंटन के लिए पात्र होंगे।

11. बगैर कोटा निर्यातक पद्धति :

(1) बगैर कोटा देशों के निर्यात और कोटा देशों को गैर-कोटा मर्शों के निर्यात में प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य मुद्रा लेव के गैर-कोटा देशों और कोटा-देशों के गैर कोटा मर्शों में निर्यातकों को आवंटन के लिए 20 (बीस) लाख रुपए को नियंत्रित नियादन के साथ आवंटन

के लिए वार्षिक स्तर का 3 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा।

(2) इस पद्धति के अंदर नहीं होने के लिए गत वर्ष 1986 से जून, 1987 की अवधि के लिए नियंत्रित नियादन 1988 के दौरान और 1987-88 एवं लातार दो वर्ष 1988-1989 के लिए उसी अवधि के लिए आवंटन को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) इस पद्धति के अंदर नियातक का मात्रा उसके नियमों के यावा-अनुमति मूल्य पर नियंत्रित किया जाएगा जो कि अधार अवधि दौरान (उदाहरणार्थ 1988 वर्ष के लिए जूलाई 1986-जून 1987) नान कोटा सामान्य मुद्रा लेव देशों को और कोटा देशों को नान कोटा मर्श गत वर्ष में तदनुसार अवधि के साथ तुलना में उसकी नियंत्रित के मूल्य में वृद्धि द्वारा समन्वित होगा। इस यावा-अनुमति पर अधारित भाग विभिन्न श्रौतों में नियातक की आवंटित की गई मात्रा का हल निकालेगा।

(4) आवंटन के लिए नियातक अधिकतम 15 देश/श्रेणी के समूह को पसन्द करने के लिए अनुमति किया जाएगा।

(5) सभी अन्य शर्तें भूतलालीन नियादन हकदारी प्रणाली के समान होंगी।

12. मंद गति वाली मर्शें :

मंद गति वाली मर्शों को अभिन्नत करने के लिए संगत वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान और सम्पूर्ण वर्ष के दौरान का नियादन हिसाब में लिया जाएगा। (1988 के लिए 1987 के प्रथम चार महीनों के दौरान और सम्पूर्ण 1986 वर्ष सात होगा।) वह मंद मंद गति वाली समझी जाएगी जिसका नियंत्रित संदर्भित अवधि के दौरान प्रथम चार महीनों के लिए अथवा पूर्ण वर्ष की संदर्भ अवधि के दौरान चिह्नित स्तर का 75% से अधिक न हो। लेकिन, सरागर वर्ष के दौरान मनदण्ड के परिवर्तन करने का अधिकार रखती है यदि मांग का रुप और वार्षिक स्तर की उपयोगिता की गति व्याप्तिशाली हो।

इस सार्वजनिक सूचना में अन्यत दी गई किसी अन्य भारत के होते हुए भी मंद गति के रूप में वर्णित मर्शों के संबंध में नियंत्रित हुआ होगा:—

(1) उत्तर राज्य अवधि नहीं होगा।

(2) नियातक को सामान्य बैंक गारंटी/पेशी धनराशि के स्थान पर एक प्रतिक्रिया पेशी धनराशि/बैंक गारंटी भेजनी होगी।

(3) पहले आए सो पहले पाए (लाल आदेश) के लिए आवेदन पत्र के मामले में नियंत्रित मर्शिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। लेकिन, यदि कोई अवेदक मंद गति वाली मर्शों के आवंटन में जो कि तेज़ गति वाली मर्शों की नियंत्रित सीमा से दो गुने अधिक होगी तो उसको तेज़ गति वाली मर्शों के लिए आवेदन सामान्य बैंक गारंटी और संधिपत्र प्रस्तुत करना होगा। एक देश/श्रेणी में एक ही दिन में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की संख्या पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यदि ऐसी मर्शों के लिए मांग उत्तर्यात्रा से अधिक है तो सरागर को मात्रिक सीलिंग के अन्तर्गत वितरण करने का अधिकार है और कोई अन्य शर्त जिसको सरकार आवश्यक समझे हकदारी के उचित वितरण के लिए लागू कर सकती है।

(4) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत सदान विलों का सत्यापन मंद गति वाली मर्शों के लिए 60 दिन तक बैध होगा।

(5) मंद गति वाली मर्शों के लिए अलग मूल्य वाली सकता है।

(6) 100 प्रतिशत निर्यात अनिमुख एककों और स्वरूप व्यापार श्रेणी के संबंध में मंद गति वाली मर्दों के लिए पैरा 8(7) में उल्लिखित शर्तें लागू नहीं होगी।

13. उन श्रेणियों का आवंटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विशिष्ट सेमा के अधीन नहीं है:-

ऐसी श्रेणी के अधीन विशिष्टिकृत मात्रा जो विशेष सेमा की शर्त के अधीन नहीं आती किन्तु यू.एस.ए के सारे श्रृंग-2 की सेमा के अधीन आती है का आवंटन सभी पद्धतियों के अधीन किसी अन्य श्रेणी की ही अपार्टि किया जाएगा। उपर्युक्त पद्धति के अधीन संवेदनशील मर्दों के आवंटन के लिए लागू सभी शर्तें ऐसी श्रेणियों के लिए भी लागू होंगी। ऐसा आवंटन ऐसी उन सभी शर्तों के अधीन होगा जो इनमें से किसी भी श्रेणी के निर्यात शुल्क करने की दिग्गज में निर्यातिकृत की जाए। ऐसे निर्यातिकृत विनिर्माता में परिवर्तन और अनियंत्रित मर्दों में भी उचित परिवर्तन के आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति समूह सेमा के अधीन दी जा सकती है।

14. हथकरघा वस्त्रों के लिए विशेष आरक्षित मात्रा का आवंटन :

“पहले आए सो पहले पाए” (लघु आदेश) पद्धति तथा केन्द्र/राज्य निगम प्रणाली के अधीन 90:10 के अनुपात में यू.एस.ए ई.सी. के सदस्य राज्य, नार्वे तथा फिलिंड के लिए हथकरघा वस्त्रों की विशेष आरक्षित मात्रा का आवंटन किया जाएगा।

15. न्यूनतम निर्यात (न्यूनतम) मूल्य:—सामान्यतः प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए सामान्यतः केवल एक न्यूनतम मूल्य होगा तथापि द्विमी गति वाली मर्दों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। जहाँ अस्कों के वस्त्रों का परिवर्तन बच्चों की अपेक्षा अवधिक संख्या में है वहाँ बच्चों के वस्त्रों के लिए कम मूल्य अनुमित है। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करें। उनको निर्धारित करने समय वे उन सभी संबंधित तर्थों पर ध्यान देंगे जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक को मंद गति वाली मर्द के रूप में अभिन्नत किया गया है या नहीं।

16. निर्यात हकदारी के सत्यापन की वैधता अवधि:—जहाँ वैधता अवधि 60 दिन प्रतिवर्षित होगी लदान विल पर सत्यापन स्वतन्त्र संविदा प्रणाली पहले आए तो पहले पाए छोटे आदेश पद्धतियों के मामले में अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

17. साखपत्र:—सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवंटन साखपत्र की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। साखपत्र प्रचलित बैंड और अपरिवर्तनीय होने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में साखपत्र, आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सभी आवंटन प्रणालियों के मामले में साख पत्र प्रमाणन के समय प्रस्तुत किए जाएं। मंद गति वाली मर्दों के लिए साखपत्रों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरा 12(1) में दिया गया है। किसी अन्य पार्टी द्वारा किया गया पोतलदान अनुमित नहीं है।

18. पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी और उनका जब्त करना:

(1) भूतकालीन निपादन पद्धति विनिर्माता/निर्यातिक पद्धति और कोटा निर्यातिक पद्धति के मामले में निर्यात को पेशगी धन या बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसे 31 मई को इससे पहले आवंटन का 50 प्रतिशत उपयोग तथा बाकी 50 प्रतिशत का उपयोग 30 सितम्बर तक कर लेना चाहिए। नीचे पैरा 2 में दिए गए के विवाए़ किसी भी अवधि में उपयोग किया गया भाग स्वतः समर्पित समझा जाएगा।

(2) भूतकालीन निपादन हकदारी, विनिर्माता निर्यातिक हकदारी तथा नान-कोटा निर्यातिक हकदारी की वैधता 30 अक्टूबर तक प्रतिवर्षित होगी। लेकिन यह वैधता जहाज पूर्णतः नियुक्त मूल्य के 20 प्रतिशत

की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त के अंत्रोन साखपत्र द्वारा समर्थित विशेष ठेकों के लिए 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा सकती है।

(3) पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) प्रणाली, संविदा प्रणाली और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में, निर्यातिक को आवेदित मात्रा के जहाज पर्यात नियुक्त मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी द्वारा समर्थित निपादन खंड देना होगा।

(4) भूतकालीन निपादन पद्धति विनिर्माता निर्यातिक पद्धति और गैर कोटा निर्यातिक पद्धति के मामले में एक निर्यातिक जो संविदा प्रणाली पहले आए सो पहले पाए तथा केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली या उपयुक्त पैरा-2 में उल्लिखित पूर्ववैधिकरण अवधि के दौरान एक विशेष अवधि के अन्तर्गत निर्यात हकदारी का 100 प्रतिशत से कम निर्यात करता है उसकी पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी। एह निर्यातिक जो 75 प्रतिशत तक लेन्द्रिन 100 प्रतिशत से कम निपादन करता है उसका अनुपातिक जब्त किया जाएगा। यदि निर्यात हकदारी आवंटन का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यात की पूरी ई.एम.डी/बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी।

(5) ये प्रावधान जब भी लागू होंगे, अतिवार्य बदला की शर्त के अधीन होंगे।

(6) मंद गति वाली मर्दों के प्रिंगे पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी पैरा 12(3) और (4) में यथा उल्लिखित लागू होंगे।

(7) केन्द्रीय राज्य निगमों के मानते में जहाँ उपयोग वैधता अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम नहीं है, निर्यातिक को निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर अगलो आवंटन अवधि के लिए समय वृद्धि लेनी होगी। ऐसी समय वृद्धि के लिए आवेदन पत्र मम्बद्ध आवंटन अवधि के अन्त से एक मास के भीतर दाखिल करने चाहिए। ऐसे मासन्तों में, नियरिकों को विशेष मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर पेशगी धन-राशि जमा करनी होगी। बैंक गारंटी देनी होगी। पूर्ण रूप से नियरित करने में अवसरत होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी पूरी तरह जब्त हो जाएगी।

(8) वे अविक्षित जिन्हें कोटे आवंटित किए जाते हैं, किन्तु वे उनका पूरा-न्यूरा उपयोग नहीं करोंगे हैं तो इस संबंध में जो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे जिन उहें और ग्राहे कोश देने से अग्राव धोयित कर दिया जाएगा।

19. पेशगी की धनराशि/बैंक गारंटी जब्त करने के विरुद्ध अधीक्षण:— आवंटित निर्यात हकदारी के उपयोग त करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जब्त करने के विरुद्ध नियरिकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए निम्नलिखित विचारित्यि लागू होंगी। परिवर्तन नियरित संप्रेषन परिवर्त द्वारा पेशगी को धनराशि नियरित बैंक गारंटी जब्त किए जाने पर संबद्ध नियरिक ऐसे जब्तोकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बम्बई को उसके विरुद्ध अधीक्षण कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीत्र से शीत्र निर्यात देंगे। यदि किसी मामले में, नियरिक वस्त्र आयुक्त के निर्यात से असन्तुष्ट हो तो वह निर्यात प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधीक्षण कर सकता है। दूसरी अधीक्षण वस्त्र मंदालय को जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गई समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

20. 30 सितम्बर से उपलब्ध मात्रा को शामिल करना:—इस सांवेजनिक सूचना में किसी भी अन्य स्थान पर निहित किसी भी नियरित को ध्यान में रखे बिना ही 30 सितम्बर को उपलब्ध शेष मात्रा चाहे वह बिना स्वर्णों से या सम्पार्ण से प्राप्त हो, एक सामान्य समूह में मिलाई गई समझी जाएगी और विभिन्न विभागों के लिए किसी आरक्षण

के बिना उम गति वर्ग के लिए संविचार प्रणाली तथा पहले वाइ. भी पूरे पाए लक्ष्य आवेदन पद्धति के अधीन उगा मात्रा को बांटा जाएगा।

21. निर्यात हक्कदारी अधिकारी का पर्यवेक्षण:—व्रत आयुक्त, दम्बई निर्यात हक्कदारी के आधिकारी से संबंधित मामलों पर दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा। एक समन्वय समिति जिसके बस्त्र आयुक्त अधिकारी होंगे, और सम्बद्ध निर्यात संबंधित परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, समय-नामय पर नीति के परिकालन की युनिक्या करेगी। विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

22. सीमा-शुल्क द्वारा निष्कासी:

(क) नियंत्रण के अधीन उत्पाद जिनमें वे रुपए भी शामिल हैं जो यूएसए में विशिष्ट सीमा के अधीन न हो।

पोतलवान की अनुमति सीमा-शुल्क प्राविकारिंद्रियों द्वारा पोतलवान के पश्चात्तों पर परिधान निर्यात संबंधित परिषद द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेपणों के लिए मूल पोत-परिषद्धन निम्नों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद:—जहाँ तक कनाडा को नियंत्रित मर्दों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों, टेलर कार्ड कमोजों के विवाय और अम्बिया को सूती हथकरघा पोशाकों यूएसए, ईसी, नार्वे, फिल्डेंड के लिए नियंत्रित वर्ग के कुछ हथकरघा वस्त्रों के लिए आरक्षित मात्रा को निर्यात का संबंध है, वहाँ सीमा-शुल्क द्वारा पोतलवान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कम्बीनेशन प्रपत्र के साथ-2 में नियंत्रण पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ग) "भारतीय मर्दों" के अधीन आने वाली भद्रों:—उन भारतीय मर्दों के बारे में जो कि डें भारतीय परम्परागत लोक प्रवर्तित उत्पाद हैं यूएसए, यूरोपीय आर्थिक समूह सदस्य राज्यों, फिल्डेंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को नियंत्रित के लिए पोतलवान सीमा-शुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण-वर्तों के आधार पर अनुमिति किया जाएगा।

23. (क) निर्यात प्रमाण-पत्र, उद्गम प्रमाण पत्र और वीसा:—संभल द्विष्टांत समझौते के अधीन निम्ननियंत्रित अपेक्षित प्रमाण-पत्र परिधान नियंत्रित संबंधित परिषद या उनके नाम में विधिवत प्राप्ति किमी अन्य परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे:—

1. यूरोपीय आर्थिक समूहों:—

(क) नियंत्रण के अधीन सभी पोशाक/युनी द्वारा मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्गम प्रमाण-पत्र।

(ख) सभी नीर नियंत्रित पोशाकों/युनी द्वारा द्वारा मर्दों के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र।

2. फिल्डेंड:—नियंत्रित मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

3. स्वीडन:—नियंत्रित मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र।

4. आस्ट्रिया:—नियंत्रण या नियाचानी की शर्त के अधीन पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

5. नार्वे:—उन व्येणियों के संबंध में जो विशिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत यात्री हैं के लिए भी निर्यात प्रमाण पत्र और मूलसं प्रमाण-पत्र।

6. कनाडा:—बुने हुए, पावरलूम, और मिल-नियमित मूल की पोशाकों जो नियंत्रण के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कमेंटिन डालर मूल्य के परेपण के लिए, निर्यात पत्र।

7. यूएसए:—(क) यूएस डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेपण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए वीसा।
(ख) यूएस डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेपण की पोशाकों, बुने हुए वस्त्रों के लिए छठ प्रभाण-पत्र।

(द) हथकरघा प्रमाण-पत्र:—नियंत्रित मर्दों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों, टेलर कार्ड कमोजों के सिवाय के कनाडा और सूती हथकरघा पोशाकों के आम्बिया ईसी, नार्वे, फिल्डेंड के लिए नियंत्रित वर्ग के कुछ हथकरघा वस्त्रों के लिए आरक्षित मात्रा को नियंत्रित के मामले में, ऐसे उत्पादों के लिए दिक्षिय समझौतों में निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्त्र समिति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

24. पूर्व सूचना द्वारा पहले के किसी भी उपकरण का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

25. संबद्ध नियंत्रित संबंधित परिषद और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त के कार्यालयों के पो निम्न प्रकार से हैं:—

1. परिधान नियंत्रित संबंधित परिषद, सहयोग विलिंग, चीयर मंजिल, 58 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019।

2. उन सथा उसी वस्त्र नियंत्रित संबंधित परिषद, 612/714, प्रणोक हाउस, 24 वाराणसी रोड, नई दिल्ली-110001।

3. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं.-11500, बम्बई-400020।

4. वस्त्र समिति, फिल्डल, 79, डा. एनी विंसेंट रोड, बम्बई-400018।

5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), बेस्ट ब्लाक, 7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022।

इ.

राजीव लोकन मिश्र,
मूल्य नियंत्रक, भारत-नियंत्रित

एच.मी. आजाद,
नियंत्रक, भारत-नियंत्रित
हुए मुक्त नियंत्रक, भारत-नियंत्रित

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th October, 1987

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 28-ETC(PN)/87

Subject :—Scheme for export under OGL 3 of garments and knitwear to USA, EEC member states, Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada from 1st January, 1988 to 31st December, 1990.

F. No. 2/95/87-E-I.—This scheme relates to the exports of certain readymade garments and knitwear items to USA, EEC Member States (FRG, France, Italy, Benelux, U.K., Irish Republic, Denmark, Greece, Portugal and Spain), Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada for the period 1st January, 1988 to 31st December, 1990.

2. Agencies for Administration of the Scheme.—
(i) Unless otherwise directed the Apparel Export Promotion Council, New Delhi will allocate export entitlements and do the necessary certification for the export of all garments and knitwear covered by this scheme, except that the entitlements for woollen knitwear would be allocated by the Wool and Woollen Export Promotion Council (W&WEPC), New Delhi. However in respect of woollen knitwear necessary certification will continue to be done by the Apparel Export Promotion Council.

List of categories of textile products covered under this scheme are available with the Apparel Export Promotion Council and W&WEPC.

(ii) Government reserves the right to make changes, as and when considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the scheme.

(iii) Export Entitlements will be allowed only to exporters who are registered with the competent registering authorities.

3. System and Quantum of Allotment.—(i) Certain categories will be identified as superfast categories, if, the exports were consistently 91 per cent or more of the level earmarked during each of the three years preceding the year under consideration. For example, for the year 1988, performance during the years 1984, 1985 and 1986 will be relevant. Textile Commissioner will identify and notify these categories.

(ii) 85 per cent of the quantities for exports under superfast categories will be allocated according to

the following system at rates indicated against each of them :

System	Percentage of annual Level
(a) Past Performance (PPE)	70
(b) Manufacturer Exporter (MEE)	10
(c) Central/State Corporation	2
(d) Non Quota Exporters (NQE)	3
	85
	—

(iii) For the remaining 15 per cent of the superfast categories, which works out to roughly 5 per cent of the total exports, at present, allocation will be made, under the Open Tender System, in order to inter alia provide opportunities to new exporters including small scale entrepreneurs. This is being introduced on an experimental basis.

(iv) For categories other than superfast categories, quantities for export will be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them :—

System	Percentage of annual Level
(a) Past Performance (PPE)	65
(b) First-Come-First-Served (Small Order) [(FCFS (SO))]	20
(c) Manufacturer Exporters (MEE)	10
(d) Central/State Corporation	2
(e) Non Quota Exporters (NQE)	3
	100
	—

(v) Government reserves the right to use flexibilities provided in the Bilateral Agreements as and when considered appropriate.

4. Division of the Allotment year and Appointment of Quantities among periods.—(i) In the case of PPE, MEE and NQE Systems, the year will be divided into two periods. The first period will be from 1st January to 31st May and the second period will be from 1st June to 30th September. A minimum of 50 per cent of the total allotment made should be utilised within the first period. The remaining 50 per cent should be utilised during the second period. Any unutilised balance at the end of each period

shall stand automatically surrendered. The allotment may however be made valid beyond 30th September as per provisions in para 18(ii) below.

(ii) In the case of (i) Central/State Corporation, (ii) Open Tender System for certain categories identified as superfast and (iii) the FCFS (Small Order) System, the year will be divided into 2 periods, namely January—May and June—September for both woven and knitted items.

Quantities under the Central/State Corporation System, Open Tender System and FCFS (Small Order) System will be distributed among the two periods in the ratio of 70 : 30. 70 per cent of the annual level will be allotted in the first period and the remaining 30 per cent in the second period. In the Open Tender System and FCFS Small Order System, quantities for USA and Canada earmarked for the first period will be opened on 1st January. Quantities for other quota countries will be opened on 15th January in order to stagger the exports.

(iii) The above percentages may be re-adjusted by the Government depending upon trends in the overseas markets.

5. Reservation of Segments.—(i) In the case of FCFS (Small Order) System, Open Tender System for superfast categories and Central/State Corporations Systems whenever knitted garments are clubbed with woven garments for allocation, 10 per cent of the annual level available would be reserved for knitted garments.

(ii) Eligibility for Past Performance Entitlement quantities available in all categories at the terminal dates will be reserved.

(iii) For woollen garments there will be reservation in terms of quantity in specified countries and categories. The policy in this regard will be announced by the Textile Commissioner.

6. Past Performance System.—(i) Agency for Calculation of Past Performance Entitlements.—The agency for calculation of the entitlement of quantities under Past Performance System in respect of each exporter will be AEPC, New Delhi. Textile Commissioner will supervise this work of AEPC.

(ii) Eligibility for Past Performance Entitlement System.—An exporter will be eligible for allotment of quantities under the Past Performance system for the year 1988 only if he has export performance by way of actual shipments in the relevant country/

category during any one of the two years viz., 1985 and 1986.

For the subsequent years 1989 and 1990, the base periods for calculating PPE would be 1986 and 1987, 1987 and 1988 respectively.

(iii) Base Period and Ceiling.—The Past Performance Entitlement for 1988 will be determined for each country/category combination pro-rata on the basis of average value of exports during the base period of 1985 and 1986. For subsequent years 1989 and 1990, the base periods would be 1986-87 and 1987-88 respectively. The pro-rata allotment of Past Performance Entitlement will be subject to a maximum ceiling in each country/category equal to the value realisation of the exporter during the base period divided by the average realisation during the base period. In case of any subsequent changes in the entitlement of any individual exporter, the entire exercise of pro-rata quantity need not be reopened but suitable adjustment will be made in the entitlement of the exporter.

- (a) All transfers of Past Performance Entitlement would only be allowed on submission of 10 per cent Bank Guarantee by the transferee.
- (b) Transferee would be allowed 60 days or till the last date of relevant period which transfer is effected, whichever is earlier, to export the transferred quantity.
- (c) Shipments against such transferred entitlement will be counted as the exports of the transferee.
- (d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country/category either in full or in part will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country/category.
- (e) A Past Performance Entitlement holder who obtains any entitlement under Open Tender System First Come First Served (Small Order) System in a particular country/category will not be eligible to effect any transfer from his Past Performance Entitlement in that country/category after he obtains such Entitlements.
- (f) The transferred entitlement in the hands of the transferee will be subject, in all other respects, to the terms and conditions as applicable to the transferer.

7. Open Tender System for Superfast Categories.—(i) Under this system, quantities will be allotted on the basis of sealed tenders. Exporters will have to submit sealed tenders indicating the premium offered to the Government on the quantities applied for. Applications will have to be made within the quantitative ceiling to be announced by the Textile Commissioner.

(ii) Allotments will be determined on the basis of the premium offered and on a day when the available quantities are over-subscribed the eligibility will be decided on the basis of higher premium bid.

(iii) Exporters would be required to export the goods on a minimum export price which would be the upset price plus the premium paid by the exporters. The upset price will be determined by the Textile Commissioner on the basis of the average unit value realisation in these categories during the previous year.

(iv) Allotments under this system will be subject to the following conditions :

- (a) Exporters should have been registered with the AEPC (or W&WEPC for woolen knitwear).
- (b) Only one application will be admissible from an exporter for one country/category for one day. However, more than one application can be made provided the total quantity covered by such applications is within the stipulated quantitative ceiling, fixed by the Textile Commissioner.
- (c) Allotments under this system will be valid for a period of 60 days. In the second period allotment will be valid for 60 days or upto 31st December, of the relevant year, whichever is earlier.
- (d) Applications for allotments should be accompanied by Demand Draft for the total premium amount payable to the Apparel Export Promotion Council.
- (e) All registered exporters irrespective of their other entitlements under any other System are eligible to apply for the bid.

8. First-come-first-served (Small Order) System.—Under this system quantities will be allotted on first-come-first-served basis in all categories other than superfast categories, against applications supported by firm contracts and L.C. L.C. however need be produced only at the time of certification. Allotment of quantities shall be made only for 87/1386 GI—2.

small orders which are within the quantitative limit fixed by the Textile Commissioner for different country/category. Such a quantitative limit will be announced in due course. The allotment under this System will be subject to the following conditions :—

- (i) The exporters should have been registered with the Apparel Export Promotion Council (or with W&WEPC for woolen knitwear) on the day of application.
- (ii) Only one application will be admissible for an exporter for one country/category for one day. However, more than one application can be made provided the total quantity covered by such application is within the stipulated quantitative ceiling.
- (iv) Allotment will be granted on first-come-for a period of 60 days. In the second period allotment will be valid for 60 days or upto 31st December of the relevant year, whichever is earlier.
- (iv) Allotment will be granted on first-come first-served basis, and on a day when available quantities are over subscribed the eligibility will be decided on the basis of higher unit price realisation.
- (v) An exporter with PPE will be eligible for applying under the System after exporting at least 50 per cent of his PPE in the relevant country/category as worked out according to para 6(iii). He will also have the option of surrendering the entire balance of PPE that he holds in the relevant country/category and then applying under FCFS (Small Order) System, provided he has not effected any transfer from his PPE in that country/category.
- (vi) Any MEE holder will have to utilise or surrender his full entitlement before becoming eligible for applying under the FCFS (Small Order) System.
- (vii) For the purpose of allotment under the FCFS (Small Order) System, an applicant should give an affidavit that none of his associate concerns as defined in paragraph 120 of the Handbook of Import-Export Procedures 1985—88 has applied for allotment under this System and also that no other proprietorship concern under his proprietorship has applied for allotment under this System. Further the applicants for 1st period allotment should also give an affidavit that none of their associate

concerns has any PPE. However, a one time affidavit in the appropriate form for the whole of the relevant year and applicable to a country or group of countries can also be taken in which the applicant will indicate one of the firms that will alone apply under FCFS (Small Order) System throughout the relevant year for a country or group of countries.

9. Manufacturer Exporter System.—(i) In this System quantities to the extent of 10 per cent of the annual leave will be allotted to manufacturer-exporters.

(ii) 8 per cent of the annual leave will be allotted to manufacturer-exporters. 2 per cent of the level will be reserved for new comers who set up manufacturing facilities during the relevant year.

(iii) For being eligible for allotment under this System a manufacturer-exporter could establish at least 100 machines and employ 150 workers.

(iv) The existing manufacturers will be eligible for allotment under the System on the basis of their existing manufacturing capacity, as registered with the Textiles Commissioner. However, they must also upgrade their manufacturing capacities by setting up at least 100 machines and employing 150 workers by 1989. The eligibility criterion for allotment under the System for existing manufacturers will be 100 machines and 150 workers as on 1st January, 1989.

(v) 50 per cent of the level reserved for existing manufacturer-exporters will be allotted on the basis of past performance and the remaining 50 per cent on the basis of the manufacturing capacity of manufacturer-exporters. The total allocation for a manufacturer-exporter under the Past Performance and the Manufacturer Exporter Systems should, however, not exceed 120 per cent of his average annual export performance during the base period (i.e. 1985 and 1986 for allotment during 1988). The total allotment of Manufacturer Exporter Entitlement to an exporter will also not exceed his manufacturing capacity.

(vi) Allotments to new manufacturer-exporters will be done on the basis of their manufacturing capacity. Unallocated quantities from the 2 per cent of the annual level reserved for the new manufacturer-exporters will be allotted firstly to existing manufacturer-exporters having more than 100 machines to the extent of overall shortfall in their manufacturing capacity and then to other existing manufacturer-exporters.

(vii) The Textile Commissioner will decide the eligibility for allotment under this System for which he will issue detailed instructions.

10. Central/State Corporations System.—For Corporations under the central or the Central/State/Union Territory Governments and Apex Cooperative Handloom marketing societies at the Central/State levels, there will be special allocation not exceeding 2 per cent of the annual level. The allocation will however be made only for direct exports by these corporations/Apex societies. The allocation under the System will be subject to the condition that the Central/State Corporation should have its own manufacturing facility. The Corporation/ Apex societies will also be eligible for allotment of quantities under other Systems, subject to the fulfilment of conditions laid down in the policy. The Textile Commissioner will determine the entitlement of the Corporation/ Apex Societies. Such Corporations will be eligible for allotment of this quota in 1989 only of their manufacturing units but at least 100 machines and 150 workers on 1st January, 1989.

11. Non-Quota Exporter System.—(i) In order to encourage exports to non-quota countries and non-quota items to quota countries 3 per cent of the annual level will be reserved for allocation to exporters with export performance of or above Rs 20 (twenty) lakhs in the GCA non-quota countries and non-quota items to quota countries.

(ii) For the purpose of calculating the entitlement under this system, export performance for the period July, 1986 to June, 1987 will be taken into account for allotment during 1988 and for similar periods of 1987-1988 and 1988-1989 for subsequent two years.

(iii) An exporter's share under this System will be determined the pro-rata value of his exports to non-quota GCA countries and non-quota items to quota countries, during the base period (e.g. July 1986—June, 1987 for the year 1988) adjusted by the increase in the value of his export when compared with the corresponding period in the previous year. Based on this pro-rata share, the quantities to be allocated to an exporter in different categories will be worked out.

(iv) An exporter will be permitted a choice upto a maximum of 15 country/category combinations for allotment.

(v) All other conditions will be the same as under PPE System.

12. Slow Moving Items.—For identification of slow moving items, performance during the first four

months of the previous year and the performance during the entire year before will be taken into account. (For 1988, the performance during first four months of 1987 and the entire year 1986 will be relevant.) An item would be termed slow moving if during the period under reference its exports have not exceeded 75 per cent of the level earmarked for the first four months or during the entire year of the reference period. Government, however, reserves the right to change the criteria during the course of the year, if warranted by the demand trend and pace of utilisation of annual levels.

Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, the following relaxations will be available in respect of items declared slow moving :—

- (i) There shall be no compulsory Letter of Credit stipulation.
- (ii) The exporter shall have to furnish 1 per cent Earnest Money Deposit or Bank Guarantee in lieu of normal Bank Guarantee/Earnest Money Deposit.
- (iii) The quantitative ceiling stipulated in the case of FCFS (Small Order) Application shall not be enforced. However, if any applicant seeks allocation in a Slow Moving item exceeding 10 times the ceiling on corresponding fast covering items, he will be required to submit the normal BG and LC required for fast moving items. There shall be no restrictions on the number of applications that can be submitted in one item in the concerned category. Should the demand for such items exceed availability, the Government, has the right to distribute the same within a quantitative ceiling and any other condition which the Government may consider necessary for proper distribution of entitlement.
- (iv) Certification of shipping bills under FCFS (Small Order) System for Slow Moving items will be valid upto 60 days.
- (v) There may be separate floor prices for Slow Moving Items.
- (vi) The conditions stipulated in para 8(vi) will not apply to Slow Moving items in respect of 100 per cent EOU's and Free Trade Zones.

13. Allocation of Categories not Subject to Specific Limit in U.S.A. and Canada.—A specified quantity under the categories not subject to specific limit but subject to overall group II limit in USA/Group-I limit in Canada will be allocated under all Systems

like any other category. All conditions applicable to allocation of sensitive items under the above Systems will also be applicable to allocation of such categories. Such allocations will also be subject to any other condition that may be stipulated in the event of limitations on exports being introduced on any of these categories. Conversion of PPE, MEE and NQE into non-restrained items using appropriate conversion factors, may be permitted within the Group ceiling.

14. Allocation of Special Quantities Reserved for Handloom Garments.—Special quantities reserved for handloom garments in USA, EEC member states, Norway and Finland will be allotted under the FCFS (Small Order) System and the Central/State Corporation System in the ratio of 90 : 10.

15. Minimum Export Price (Floor Prices).—Normally, there shall be only one floor price for each country/category. However, a lower floor price may be fixed for Slow Moving Items. A lower price for children's garments where conversion of adult garments to higher number of children's garments is permitted. The Textile Commissioner will prescribe such prices. In determining them he will take into account all relevant factors including the fact whether a particular item has been identified as Slow Moving or not.

16. Validity Period of Certification of Export Entitlement.—A certification on the shipping bills shall be valid for a period of 30 days except in the case of Open Tender System and First-Come-First-Served Small Order System where the validity period will be restricted upto 60 days.

17. Letter of Credit.—The allocation for all garments and knitwear will be made on basis of credit terms. Letter of Credit should be operative, valid and irrevocable. In the case of all Systems of Payment, Letter of Credit should be produced at the time of obtaining certification. Letter of Credit will not be required for slow moving items declared as such in terms of para 12(i). Third party shipments are not allowed.

18. Earnest Money Deposit/Bank Guarantee and Forfeiture thereof.—(i) In the case of PPE, MEE and NQE Systems exporter will not be required to furnish Farmer Money Deposit or Bank Guarantee. However, he must utilise 50 per cent of the allocation on or before 31st May and the remaining 50 per cent by 30th September. The unutilised portion during any period will automatically stand surrendered except as provided in para (ii) below :

(ii) The validity of PPE, MEE and NQE would be restricted to 30th September. However, validity can be extended upto 31st December against specific

contracts backed by Letter of Credit subject to submission of Earnest Money Deposit or Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of FOB value.

(iii) In the case of FCFS (Small Order) System, Open Tender System and Central/State Corporation System, an exporter shall be required to give performance bond backed by Earnest Money Deposit, Bank Guarantee @ 5 per cent of the FOB value on the quantities applied for.

(iv) An exporter who exports less than 100 per cent of the export entitlement in a particular period under Open Tender System, FCFS (Small Order) or Central/State Corporations systems or during the revalidation period as indicated in para (ii) above in case of PPE, MEE and NQE System or transferred PPE will be liable to forfeiture of EMD/BG. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 100 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable to forfeiture of EMD/BG in full.

(v) These provisions will be subject to conditions of force majeure wherever these arise.

(vi) For slow moving items, the Earnest Money Deposit/Bank Guarantee as indicated in paras 12(ii) and (iii) will be applicable.

(vii) In the case of Central/State Corporations where utilisation is not less than 75 per cent within the validity period exporter will have the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for such extension would be filed within one month of the end of the relevant allotment period. In such cases exporter will have to furnish EMD/BG at double the normal rate for balance quantity. In the case of his failure to export fully, the EMD/BG will be liable to be forfeited in full.

(viii) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

19. Appeal against Forfeiture of EMD/BGs.—For the purpose of giving the consideration to representation made by the exporters against forfeiture of EMD/BG for non-utilisation of allotted export entitlement, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD/BG by the AEPC the exporter concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within 15 days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upto receipt of the representation

give a ruling as early as possible. If in any case the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Ministry of Textiles and will be dealt with by the Appellate Committee constituted by the Government.

20. Merger of available Quantities on 30th September.—Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, all balance quantities available as on 30th September from unallocated levels or surrenders from all Systems shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the Tender system for superfast categories and under the FCFS (Small Order) System for the remaining items without any reservation for different segments.

21. Supervision of Allocation of Export Entitlement.—Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day-to-day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Coordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and representatives of the concerned EPC as Members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

22. Clearance by Customs.—(A) Products under restraint including items not subject to specific limits in USA.—Shipments will be allowed by Customs Authorities at the ports of shipments after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the AEPC.

(B) Handloom Garments.—In so far as exports of all handloom garments except Tailored Collar shirts corresponding to restrained items in Canada, Cotton handloom garments to Austria, special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories to USA, EEC, Norway, Finland, shipments will be permitted by the Customs on the basis of Inspection Endorsement by the Textile Committee in part 2 of the combination form.

(C) Garments falling under India Items.—In respect of India Items which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Norway and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

23. (A) Export Certificate, Certificate of Origin and Visa.—The following certificates required under the relevant bilateral textile agreements will be issued by AEPC or any other agency duly authorised in this behalf :—

- (i) EEC—(a) Export Certificates and Certificate of origin for all garments|knitwear items under restraint.
- (b) Certificates of Origin for all non-restrained garments|knitwear items.
- (ii) Finland.—Export Certificates for restrained items.
- (iii) Sweden.—Export Certificates for restrained items.
- (iv) Austria.—Export Certificates for garments subject to restraint or surveillance.
- (v) Norway.—Export certificate and certificate of origin in respect of categories subject to specific limits.
- (vi) Canada.—Export Certificate for garments of knitted, powerloom and mill made origin which are subject to restraint export for consignments valued at Canadian \$ 500 or less.
- (vii) USA.—Visa for all garments|knitwear consignments valued over US \$ 250.

(B) Handloom Certificate.—In the case of export of all handloom garments except Tailored Collar shirts corresponding to restrained items to Canada, cotton handloom garments to Austria and special quantities reserved for Handloom Garments in some

of the restrained categories to EEC, Norway and Finland the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the bilateral Agreements for such products.

23. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

24. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. The Apparel Export Promotion Council, Sahyog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi.
2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-1.
3. Office of the Textile Commissioner, Post Box 11500, Bombay-400028.
4. Textile Committee, "Crystal", 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.
5. Development Commissioner (Handicrafts), West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

Sd/-

R. L. MISRA, Chief Controller
of Imports & Exports

H. C. AZAD, Controller
of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

